

संपादकीय

बचपन की डोली और उजड़ता भविष्य

गुना जिले से आई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-6 की रिपोर्ट चौंकाने वाली नहीं, बल्कि डराने वाली है। कानून है, पुलिस है, महिला एवं बाल विकास विभाग है और सरकार के तमाम प्रयास हैं, लेकिन बाल विवाह की परंपरा थमने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट कहती है कि 20 से 24 वर्ष की हर चौथी युवती का विवाह 18 साल की कानूनी उम्र से पहले हो चुका है। यह अनुपात 25.9 प्रतिशत है। पांच साल पहले यह 28.1 प्रतिशत था। यानी कमी तो आई, लेकिन राज्य के 20 प्रतिशत औसत से गुना अभी भी काफी ऊपर है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर पुरुषों के आंकड़ों में सामने आई है। 25 से 29 वर्ष की उम्र के 39 प्रतिशत पुरुषों की शादी 21 साल की कानूनी उम्र पूरी होने से पहले हुई है। पहले के सर्वे में यह अनुपात 21.8 प्रतिशत था। यानी पांच साल में 17.2 प्रतिशत अंक को बढ़ोतरी हुई है। राज्य का औसत 25 प्रतिशत है।

शादी जल्दी तो मातृत्व भी जल्दी और फिर कुपोषण की मार। जिले में 15 से 19 वर्ष की 8.5 प्रतिशत किशोरियाँ सर्वे के समय या तो मां बन चुकी थीं या गर्भवती थीं। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 5.5 प्रतिशत था। यानी पांच साल में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश का औसत 5.6 प्रतिशत है। कम उम्र में मां बनने के कारण महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ होता और उस पर मातृत्व का बोझ डाल दिया जाता है। इससे महिला का हीमोग्लोबिन कम होता है, हड्डियाँ कमजोर होती हैं और बच्चा भी कम वजन का पैदा होता है। यही बच्चा आगे चलकर कुपोषित होता है और यही चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

सवाल है कि बच कानून है तो विवाह हो कैसे रहे हैं? उत्तर है, परंपरा और गरीबी। पुलिस को खबर लगती है तो वह मौके पर पहुंचती भी है, लेकिन लोग रातोंरात शादी करा देते हैं या दूसरे जिले में ले जाकर विवाह कर देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पता चलने पर भी कई बार सामाजिक दबाव में वह चुप रह जाती है। लोग सोचते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है, जल्दी शादी कर दो तो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लड़के के मामले में सोचते हैं कि जल्दी शादी कर देंगे तो मजदूरी में हाथ बंट जाएगा और घर संभालेगा। शिक्षा की कमी इस सोच को और मजबूत करती है। जिले में 15 से 49 वर्ष की केवल 18.9 प्रतिशत महिलाओं ने दस या उससे अधिक वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी की है, जबकि प्रदेश में इसका औसत 33.7 प्रतिशत है। जब शिक्षा नहीं होगी तो जागरूकता कहाँ से आएगी?

बाल विवाह की चर्चा में लड़कियों पर फोकस रहता है, लेकिन गुना में पुरुषों का आंकड़ा भी बड़ा सवाल है। 25 से 29 वर्ष के 39 प्रतिशत पुरुषों की शादी 21 साल से पहले हुई है। कम उम्र का लड़का न परिवार संभालने लायक होता है, न रोजगार के लायक। फिर वह भी मजदूरी करता है और गरीबी में पूरा परिवार फँस जाता है। केवल कानून का डंडा काफी नहीं है। शिक्षा मजबूत करनी होगी, गांव-गांव में बैठियों की शिक्षा पर जोर देना होगा और लोगों को कम उम्र में विवाह के दुष्परिणाम समझाने होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग को किशोरियों की काउंसिलिंग और पुलिस प्रशासन को विशेष निगरानी करनी होगी। गुना की रिपोर्ट पूरे मध्य प्रदेश के लिए चेतावनी है। बैठी को बचपन में ही दुल्हन बनाने की परंपरा रोकनी होगी, तभी हर बच्ची को अपना बचपन जीने का अवसर मिलेगा।

आजकल

विकास के नाम पर 2.89 लाख पेड़ों पर मंडराता संकट

भोपाल की पहचान उसकी झीलों और हरियाली है, लेकिन मास्टर प्लान 2047 में प्रस्तावित 791 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क ने इस पहचान पर गंभीर खवाल खड़ा कर दिया है। अनुमान के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क के लिए करीब 2 लाख 89 हजार पेड़ों की बलि चढ़ सकती है। हाल ही में एनएचपीआई की 16.44 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए ही लगभग 6 हजार पेड़ काटे गए थे, यानी औसतन 365 पेड़ प्रति किलोमीटर। इसी औसत से 791.42 किलोमीटर के नेटवर्क के लिए 2,88,868 पेड़ों का नुकसान तय है।

प्रशासन का तर्क है कि बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सड़कों जरूरी हैं, लेकिन समस्त यह है कि क्या हरियाली की कीमत पर किया गया विकास सच में विकास कहलाएगा या यह शहर के फेफड़ों पर सीधा हमला है।

इस योजना का सबसे कमजोर पक्ष बिना ग्राउंड सर्वे के नक्शे पर लाइन खींच देना है, जिसे एक्सपर्ट ओवरलैपिंग मार्किंग कह रहे हैं। कई जगहों पर पहले से मौजूद अच्छी-भली सड़कों को ही नई प्रस्तावित सड़क के रूप में दिखा दिया गया है। मैनिट भोपाल के प्लानिंग विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कागज पर सड़क बनाना आसान है, लेकिन जमीन पर उसकी कीमत पेड़ों को चुकानी पड़ती है।

पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी. पांडे और राशिद नूर जैसे विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी बड़ी कटाई से शहर का तापमान बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। भोपाल मास्टर प्लान 2005 में भी ग्रीन बेल्ट की बचाने का वादा था, लेकिन हकीकत में उन पर कॉलोनियां बन गईं। अब 2047 में वही गलती दोहराई गई तो राजधानी सांस लेने लायक भी नहीं बचेगी।

एक पेड़ की कीमत 1450 रुपये तय करना इस पूरे सिस्टम की बड़ी खामी दिखाता है। 50 साल पुराने बरगद या पीपल की कीमत सिर्फ़ मुआवजे से नहीं आंकी जा सकती। समाधान यही है कि सड़क भी बने और पेड़ भी बचें। इसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एंक्लांटेड रोड, ग्रीन कॉरिडोर, एक के बदले दस पेड़ लगाने और ट्रांसप्लेंटेशन की नीति को सख्ती से लागू करना होगा। वरना यह विकास भोपाल को झीलों के शहर से धूल का शहर बना देगा।

देश

के गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने जब सहकार से समृद्धि का शंखनाद किया, तो वह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता के लिए एक नए युग का आरंभ था। यह संकल्प दुग्ध क्रांति का है, गांव की समृद्धि का है, जरूर मुक्त थाली का है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का भी है। अब समय आ गया है कि सरकार के साथ-साथ हर नागरिक भी इस महाअभियान में शामिल हो।

गुजरात ने सहकारिता के बल पर श्वेत क्रांति करके दुनिया को दिखा दिया कि जब किसान एक साथ आता है तो क्या चमत्कार हो सकता है। वही चमत्कार अब मध्य प्रदेश में दोहराने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में दुध की अपार संभावनाएँ हैं। यहां के गांवों में आज भी हर घर में गाय पाली जाती है। जरूरत है कि इसे वैज्ञानिक तरीके से सहकारिता से जोड़ा जाए। जब गांव में दुग्ध सहकारी समितियां बनेंगी तो किसान को अपने दूध का सही दाम मिलेगा, बिचौलिया खत्म होगा और गांव का पैसा भी घर में ही रहेगा। यह श्वेत क्रांति का दूसरा अध्याय होगा, जिसका केंद्र मध्य प्रदेश बन सकता है। अभी तक हम गोपालन को केवल दूध तक सीमित रखते थे, लेकिन इस अभियान ने

गोपालन को पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की संभावना पैदा की है। एक गाय केवल दूध ही नहीं देती, वह गोबर देती है, गोमूत्र देती है और समृद्धि के अनेक रास्ते खोलती है। जब गांव में गोपालन बढ़ेगा तो दूध के साथ घी, मक्खन, पनीर, खोवा और छाछ जैसे उत्पाद भी गंव बनेंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा और गांव शहरों पर निर्भर नहीं रहेगा। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक भी होगा। जब किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा और जब गांव समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा।

आज बाजार में सबसे बड़ा संकट मिलावट का है। दूध में पानी, घी में डालड़, पनीर में केमिकल और मसालों में रंग, यह मिलावट धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रही है। सहकारिता के इस अभियान के माध्यम से जब सामाजिक समितियों से शुद्ध देसी उत्पाद लोगों तक पहुंचेंगे तो आम आदमी इस जहर से बच सकेगा। शुद्ध घी और शुद्ध पनीर जैसे उत्पादों की उपलब्धता से परिवार के स्वास्थ्य में सुधार

शेरिंग तोबरो

27 जुलाई 2019 को मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

दस महीने पहले भूटान के चुनावों में मेरी पार्टी पराजित हो गई थी और संसद में पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मैं न तो प्रधानमंत्री था और न ही सांसद; मैं पीएम मोदी से एक आम नागरिक के तौर पर मिला।

मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने उनसे कहा कि वे हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे-सिर्फ इसलिए नहीं कि वे उम्र में बड़े हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने मेरे साथ वैसा ही स्नेह दिखाया जैसा एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ करता है।

फिर मैंने उनसे एक और बात कही: मैंने उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा। मैंने बताया कि हमारे इलाके में, ज्ञानी और नेक शासकों को लंबे समय से ऐसा ही माना जाता रहा है।

मेरी अपनी ही बातों ने मुझे हैरान कर दिया। बाद में, मैंने सोचा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा। क्या मैं भावनाओं में बह गया था? क्या मैं गलत था?

बाद में, जब मैंने अपनी कही बातों पर विचार किया, तो जवाब स्पष्ट हो गया। पीएम मोदी को विष्णु का अवतार मानना सही था।

मैंने उन्हें लगभग 13 वर्षों तक गुजरात का शासन चलाते देखा था, जब राज्य विकास, अवसंरचना, निवेश और कार्यान्वयन के मामले में देश के लिए एक मिसाल बन गया था। फिर मैंने उन्हें उस महत्वाकांक्षा को पूरे भारत के स्तर पर ले जाते देखा: विनिर्माण, विदेशी निवेश, वित्तीय समावेश, स्वच्छता, तकनीक और अवसंरचना और इन सबके मूल में था सेवा और काम को पूरा करने पर लगातार जोर।

मैंने उस जनसेवक को भी देखा: अनुशासित, ऊर्जावान और असाधारण रूप से मेहनती। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह थी - देशवासियों की सेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण।

लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्होंने भारतीयों में खुद पर और अपने देश पर एक सशक्त विश्वास जगाया। वे भारत को लेकर ज्यादा गर्व महसूस करने लगे, इसकी संभावनाओं को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी हुए और दुनिया में इसकी जगह को लेकर ज्यादा आश्वस्त हुए।

मेरे लिए, ये एक ज्ञानी व नेक शासक के गुण थे।

भूटान की बौद्ध परंपरा में, हम 'रिग्सुम गोनपो' का सम्मान करते हैं, जो सभी जीवों की मुक्ति के लिए समर्पित बोधिसत्त्वों की एक त्रिमूर्ति है। मंजूश्री ज्ञान की प्रतीक हैं, अर्चलोकितेश्वर करुणा का; और वज्रपाणि साहस का।

मेरे लिए, ज्ञानी नेतृत्व का मतलब है, निस्वार्थ सेवा के जरिए इन तीन गुणों- बुद्धिमत्ता, करुणा और साहस-का उपयोग करना।

डॉ. शिशिर उपाध्याय

जम्मू-

कश्मीर में एक परंपरा सदियों से चली आ रही है। छह महीने श्रीनगर राजधानी और छह महीने जम्मू राजधानी। यह केवल राजधानी बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आर्थिक संतुलन का सबसे बड़ा प्रयोग है। अक्टूबर से मार्च तक जब बर्फ श्रीनगर को ढक लेती है, तब पूरी सरकार फाइलों, ट्रकों और कर्मचारियों के साथ जम्मू आ जाती है और फिर गर्मियों में वापस श्रीनगर चली जाती है। हमने जब स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और नौकरशाहों से बात की तो अधिकांश का यही कहना था कि दरबार मूव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

इस परंपरा की शुरुआत डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह के समय से मानी जाती है। कारण था मौसम। श्रीनगर में सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, झेलम जम जाती है और कामकाज ठप हो जाता है। जम्मू का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहता है, इसलिए दरबार को जम्मू स्थानांतरित किया जाता था। यह परंपरा आज भी जीवित है और अब इसका स्वरूप आर्थिक हो गया है। सरकार के साथ हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है और इससे दोनों क्षेत्रों में पैसों का प्रवाह बना रहता है। जब सरकार चलती है तो व्यापार चलता है।

स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि दरबार के साथ ही लक्ष्मी चलती है। जब

नईदुनिया

आज के दौर के लिए एक अवतार



आज मैं इन गुणों को पीएम मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन में सबसे साफ़ तौर पर एक साथ आते हुए देखता हूँ।

बुद्धिमत्ता की शुरुआत बेहतर भविष्य के स्पष्ट विजन से होती है। और उन्होंने भारत को एक विजन दिया है: आज़ादी के ठीक एक सदी बाद, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना। ‘विकसित भारत’ के साथ, उन्होंने उस विजन को एक नाम, एक समय-सीमा और एक राष्ट्रीय मिशन दिया है।

करुणा की शुरुआत दूसरों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को समझने से होती है। और ‘विकसित भारत’ ठीक यही प्रतिबिंबित करता है: एक मजबूत, समृद्ध और विकसित देश के लिए 1.4 अरब भारतीयों की सामूहिक महत्वाकांक्षा। ‘सबका साथ, सबका विकास’ उस आकांक्षा को दर्शाता है: सभी एक साथ, सबका विकास।

साहस की शुरुआत विजन को वास्तविकता में बदलने के संकल्प से होती है। मानव संसाधन बनाना, निवेश आकर्षित करना, अवसंरचना को आधुनिक बनाना और सबसे बढ़कर, शासन को बेहतर बनाना-इन सबके लिए मुश्किल फ़ैसले लेने और लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। विज़न बनाना आसान है। बदलाव लाना नहीं।

और निस्वार्थ सेवा इन गुणों को एक साथ जोड़ती है। ‘विकसित भारत’ किसी एक नेता या चुनावी चक्र के बारे में नहीं है। यह इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के बारे में है। ‘सबका प्रयास’ के जरिए, पीएम मोदी ने हर भारतीय से न सिर्फ़ इस मिशन का समर्थन करने, बल्कि इसे बनाने में भाग लेने का भी आह्वान किया है।

निःसंदेह, यह उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने भारत को सिर्फ़ एक मंजिल ही नहीं दी है। उन्होंने भारतीयों को उस विज़न

भी इस उदार साझेदारी को बनाए रखा।

और यही कारण है कि जब मैं 2024 में दोबारा सत्ता में आया, तो उन्होंने हमारी 13वीं योजना के लिए भारत की मदद को दोगुना करके ₹10,000 करोड़ कर दिया।

आज, बी4बी पूरे भूटान में दिखाई देता है-स्कूलों और अस्पतालों में, सड़कों और पुलों में, पनबिजली और तकनीक में, कृषि और उद्यम में।

लेकिन बी4बी का असर सबसे ज्यादा वहाँ दिखता है जहाँ भारत, महामहिम राजा के ‘गोलेफू माइंडफुलनेस सिटी’ (जीएमसी) के विज़न का समर्थन कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत की ओर से पूरा समर्थन देने का वादा किया है, और यह वादा अब रेल लिंक, सीमा अवसंरचना और बेहतर हवाई व डिजिटल संपर्क के रूप में साकार हो रहा है।

इससे भी अहम बात यह है कि भारतीय कारोबारियों ने पीएम मोदी के स्पष्ट समर्थन से प्रेरणा ली है। टाटा पावर, अडानी समूह, जेएसडब्ल्यू एनजी और अन्य कंपनियाँ भूटान के आर्थिक बदलाव में निवेश कर रही हैं। जबकि भारत के बड़े कारोबारी जीएमसी में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। इसलिए, जब महामहिम राजा ने भूटान के लिए पीएम मोदी के असाधारण योगदान को देखते हुए उन्हें हमारे सर्वोच्च सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ़ ड्रुक ग्यालपो’ से सम्मानित किया, तो सभी भूटानी बहुत खुश हुए। वे यह सम्मान पाने वाले पहले और एकमात्र विदेशी राजनेता हैं।

मेरे लिए, उनका प्रभाव बहुत व्यक्तिगत भी रहा है। मैं लंबे समय से पीएम मोदी को बड़े भाई की तरह मानता रहा हूँ और इन सालों में उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है। उन्हें मुझे कभी निर्देश देने की ज़रूरत नहीं पड़ी; एक जनसेवक के तौर पर उनका उदाहरण ही मेरे लिए निर्देश रहा है।

आज, जब पीएम मोदी सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 साल पूरे कर रहे हैं, तो मुझे 2019 की वह प्रे़क बातचीत याद आती है-और हमारी अगली मुलाकात, जो 14 मार्च 2024 को हुई थी। तब तक, मैं फिर से प्रधानमंत्री बन चुका था। मैंने दिल्ली में अपने बड़े भाई से मुलाकात की; यह मुलाकात उन्हें यह बताने के पाँच साल बाद हुई थी कि मैं उन्हें विष्णु का अवतार मानता हूँ।

मैंने उनसे कहा कि मैंने पाँच साल पहले जो कहा था, उस पर मैंने बहुत गहराई से सोचा है और इस बात पर भी मनन किया है कि क्या मैं गलत था। मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं सही था। इतना ही नहीं। अब मुझे यह भी पता था कि वे कौन से अवतार हैं।

विष्णु का आखिरी अवतार-जो अव्यवस्था को दूर करने, धर्म की स्थापना करने और नई शुरुआत लाने से जुड़ा है।

कल्कि।

(लेखक भूटान के प्रधानमंत्री हैं ।)

दरबार चलता है तो बाजार चलता है



केवल किराए की आय से अपना साल भर का खर्च निकाल लेते हैं। श्रीनगर में भी यही स्थिति है। पर्यटन और सरकारी कर्मचारियों के कारण वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

कुछ लोग दरबार मूव को फिजूलखर्ची भी कहते हैं। सरकार को हर साल स्थानांतरण पर करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। फाइलों के गुम होने का डर रहता है, कामकाज कुछ दिनों के लिए ठप होता है और इंटरनेट, फाइल सिस्टम के इस युग में इस परंपरा की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस खर्च को केवल खर्च के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक निवेश है, जो दो क्षेत्रों को जोड़ता है। अगर सरकार केवल एक ही जगह रहेगी तो दूसरा क्षेत्र उपेक्षित महसूस करेगा और

आर्थिक असमानता बढ़ेगी। दरबार मूव इस असमानता को कम करता है। जम्मू और कश्मीर दो अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, दो अलग-अलग जलवायु हैं और दो अलग-अलग बाजार हैं। दरबार मूव इन दोनों को एक धागे में पिरोता है। जम्मू

के लोग जब श्रीनगर जाते हैं तो वहां की संस्कृति को समझते हैं और श्रीनगर के लोग जब जम्मू आते हैं तो यहां के व्यापार को समझते हैं। यह आदान-प्रदान केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक भी है। नौकरशाहों का कहना है कि इससे पूरे प्रदेश का संतुलित विकास होता है। एक क्षेत्र में छह महीने सरकार रहने से वहां की समस्याओं को नजदीक से देखा जा सकता है और उनका तुरंत समाधान किया जा सकता है।

अब समय बदल गया है। ई-फाइल और ई-ऑफिस का युग आ गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव आया है। सरकार ने एक बार दरबार मूव को रोकने का निर्णय भी लिया था, लेकिन स्थानीय भावना और आर्थिक कारणों से इसे फिर से जारी

रखना पड़ा। व्यापारी वर्ग का मानना है कि अगर यह परंपरा पूरी तरह बंद हो गई तो दोनों शहरों की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। जम्मू के कई बाजार तो केवल दरबार के भरौसे ही चलते हैं और श्रीनगर में भी सरकारी कर्मचारियों के कारण बाजार में जान आती है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ इस परंपरा को जारी रखना जरूरी है।

आवश्यकता इस बात की है कि दरबार मूव को और अधिक व्यवस्थित किया जाए। खर्च को कम करने के लिए डिजिटल शिफ्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन भौतिक उपस्थिति भी बनाए रखी जाए। सरकार को चाहिए कि शिफ्टिंग के समय को एक उत्सव के रूप में मनाए, ताकि व्यापार को और बढ़ावा मिले। स्थानीय नागरिकों का सुझाव है कि दोनों राजधानियों में स्थायी सचिवालय रहें, लेकिन मंत्री और प्रमुख अधिकारी छह-छह महीने दोनों जगह रहें। इससे खर्च भी कम होगा और आर्थिक संतुलन भी बन रहेगा।

दरबार मूव केवल फाइलों का आना-जाना नहीं है। यह जम्मू-कश्मीर की आत्मा है। यह आर्थिक परिवर्तन का वह मार्ग है, जो सदियों से दोनों क्षेत्रों को जोड़ता आ रहा है। जब दरबार चलता है तो बाजार चलता है, जब बाजार चलता है तो रोजगार चलता है और जब रोजगार चलता है तो विकास चलता है। इसलिए यह परंपरा केवल परंपरा नहीं है, बल्कि आर्थिक संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेगा। पशुपालन, डेयरी उद्योग और जैविक खेती मिलकर गांवों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

यह अभियान केवल सरकार का नहीं, प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता का महायज्ञ है। जब तक हर व्यक्ति इसमें अपनी आहुति नहीं देगा, तब तक यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। हर गांव में सहकारी समिति हो, हर समिति में शुद्धता और ईमानदारी का संकल्प हो और हर किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिले, यही इस अभियान की सफलता का आधार होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, उसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जमीन पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी जनता की है कि वह भी इस मंत्र को अपने जीवन में उतारे। आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश के गांवों में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, खेतों में जैविक फसलें लहलहाएंगी और घरों तक शुद्ध भोजन पहुंचेगा, तब सहकार से समृद्धि का सपना साकार होता दिखाई देगा। यह केवल दुग्ध क्रांति नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव की संभावना है। जरूरत केवल इस संकल्प को ईमानदारी, निरंतरता और जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाने की है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)